उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) देश में कुल जिलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) किसी राज्य के जिलों का औद्योगीकरण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार ने नियंत्रणों को हटाने और कार्यविधियों को सुस्पष्ट बनाने के लिए औद्योगिक नीति को उदार बनाया है ताकि सरकार की स्थापना-स्थल और पर्यावरण संबंधी नीति के अनुसार उद्योग स्थापित किए जा सकें जिनके स्थापना स्थलों का निर्णय अलग-अलग उद्यमियों द्वारा किया जाएगा।

विवरण

देश में कुल जिलों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	अरूणाचल प्रदेश	12
3.	असम	23
4.	बिहार	42
5.	गोआ	2
6.	गुजरात	19
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	20
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	45
13.	महाराष्ट्र	31
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	27
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	30
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	22
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	63
25.	पश्चिम बंगाल	17

बिहार में रुग्ण लघु उद्योग

557. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कितने लघु उद्योगों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(ख) उद्योग को रुग्ण घोषित करने का मापदंड क्या है,

(ग) क्या वास्तविक रूप से रुग्ण और जो वास्तविक रूप से रुग्ण उद्योग नहीं हैं उनकी अलग से पहचान करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम: (क) भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार बिहार में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 7823 थी, जिनपर 91.84 करोड़ रु. बकाया बैंक ऋण था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक लघु औद्योगिक एकक को रुग्ण माना जायेगा, जब

1. यदि इसका कोई उधार खाता "संदेहपूर्ण" अग्रिम राशि हो गया है अर्थात, कोई इसके किसी उधार खाते में मूल अथवा ब्याज 2½ (ढाई) वर्ष की अवधि से ज्यादा समय तक अतिदेय रहा हो, और

2. पिछले दो लेखा वर्षों के दौरान इसके अधिकतम शुद्ध मूल के 50% अथवा इससे अधिक संचित नकद हानियों के कारण शुद्ध मूल कम हो गया हो।

(ग) और (घ) बैंकर, जो पुर्स्थापना पैकेज तैयार करते हैं, को उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार एकक की प्रमाणिकता के बारे में स्वयं आशवस्त होना होगा।

Government Directive to PSUs on Wage Structure

558. SHRI SOM PAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether government have issued a directive to the major Public Sector Undertakings to evolve their own wage structures and to do away with the existing uniform wage pattern;

(b) if so, what is the rationale thereof;

(c) whether Government have studied the likely impact of the measure on the industrial relations and viability of these units; and

(d) if so, what are the details thereof?